*एमएसएमई - ऋण देने में विश्वास बढ़ाकर ऋण अंतर को पाटना**

श्री स्वामीनाथन जे.

श्री सुरेश कुमार सिंघल, अध्यक्ष एफटीसीसीआई, श्री आर. रवि कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एफटीसीसीआई, श्री के. के. माहेश्वरी, उपाध्यक्ष, एफटीसीसीआई, श्री मीला जयदेव, संयोजक, एफटीसीसीआई सीईओ फोरम, आज यहाँ एकत्रित मुख्य कार्यपालक अधिकारीगण, देवियो और सज्जनो। आप सभी को शुभ संध्या। मुझे आज आपसे एक ऐसे विषय पर बात करते हुए खुशी हो रही है जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहा है - एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) की महत्वपूर्ण भूमिका और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को ऋण देने में विश्वास अर्जित करने का महत्व। पिछले कुछ वर्षों में, मुझे एमएसएमई इकाइयों के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिला है, और मैंने उनकी क्षमता और उनके संघर्ष दोनों को देखा है। मैं अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक युवा अधिकारी के रूप में चहल-पहल वाले पीन्या औद्योगिक क्षेत्र में तैनात था, वहाँ मैंने एमएसएमई को परिभाषित करने वाली ऊर्जा और समुत्थानशीलता के साथ-साथ उनके सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को भी देखा। बाद में, करियर के मध्य में, एसबीआई के मिड कॉरपोरेट्स ग्रुप में काम करते हुए मेरे अनुभव में वृद्धि हुई, जहाँ मैंने आगे यह बात समझी कि कैसे समय पर और पर्याप्त ऋण तक पहुँच- इन व्यवसायों को बदल सकती है। इन अनुभवों ने मुझे एमएसएमई के लिए ऋण अंतर को पाटने के महत्व के बारे में गहराई से अवगत कराया है - एक ऐसा कार्य जिसके लिए न केवल नवोन्मेषी समाधानों की आवश्यकता है, बल्कि ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच एक समान विश्वास को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता की भी आवश्यकता है।

जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमएसएमई क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है और पर्याप्त रोजगार अवसर प्रदान करता है। ये उद्यम, बड़े उद्योगों के लिए आवश्यक सहायक इकाइयों के रूप में काम करते हैं तथा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लगभग 6.3 करोड़ इकाइयों के साथ,[1] एमएसएमई भारत के अंकित सकल घरेलू उत्पाद में लगभग एक तिहाई योगदान देते हैं और देश के निर्यात में 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं।[2] इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, 22 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन करते हैं[3] और भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने की अपार क्षमता रखते हैं। इस प्रकार, एमएसएमई क्षेत्र न केवल आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देता है बल्कि गरीबों का उत्थान भी करता है, आजीविका प्रदान करता है और पूरे देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, इस क्षेत्र से हम जो आम शिकायत सुनते हैं, वह यह है कि उन्हें समय पर और पर्याप्त औपचारिक ऋण प्राप्त करना मुश्किल लगता है। यह चुनौती उनकी वित्तीय और कारोबारी व्यवहार्यता पर सूचना विषमता जैसे कारकों के कारण हो सकती है, और एमएसएमई क्षेत्र के भीतर आज भी सीमित औपचारिकता के कारण भी हो सकती है। कई एमएसएमई के पास व्यापक वित्तीय रिकॉर्ड या क्रेडिट स्कोर का अभाव है, और कुछ मामलों में, उनके पास आवश्यक वित्तपोषण के पैमाने का समर्थन करने के लिए पर्याप्त संपार्श्विक नहीं हो सकता है। इन मुद्दों के परिणामस्वरूप इन इकाइयों की ऋण आवश्यकताओं और उपलब्ध आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर होता है - जिसे क्रेडिट गैप के रूप में जाना जाता है। पांच वर्ष पहले, आरबीआई द्वारा गठित एमएसएमई पर विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: यू.के. सिन्हा) की रिपोर्ट ने इस ऋण अंतर के ₹20 से ₹25 लाख करोड़ के बीच होने का अनुमान लगाया था।

आरबीआई की पहलें

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी ओर से कई लक्षित उपायों के माध्यम से एमएसएमई को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल करने को लगातार प्राथमिकता दी है। प्रमुख

* (16 नवंबर 2024 को हैदराबाद में आयोजित फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीईओ फोरम में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे. का भाषण)

[1] सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। (2023)। वार्षिक रिपोर्ट 2023-24। https://msme.gov.in/sites/default/files/FINALMSMEANNUALREPORT2023-24ENGLISH.pdf (पृष्ठ 23) से लिया गया।

[2] सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। (22 जुलाई 2024)। सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई का योगदान [प्रेस विज्ञप्ति]। प्रेस सूचना ब्यूरो। https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2035073 से लिया गया।

[3] 3 उद्यम पंजीकरण पोर्टल (12 नवंबर 2024 तक का डेटा) https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm

पहलों में से एक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) दिशानिर्देश हैं, जो सूक्ष्म उद्यमों के लिए बैंकों के समायोजित निवल बैंक ऋण के 7.5 प्रतिशत के उप-लक्ष्य को अनिवार्य बनाता है, जबकि एमएसएमई को दिए जाने वाले सभी ऋण पीएसएल के अंतर्गत आते हैं। आरबीआई ने बैंकों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए ₹10 लाख तक के ऋण के लिए संपार्श्विक पर जोर न देने और वित्तीय संस्थाओं को सीजीटीएमएसई योजना के तहत ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करके संपार्श्विक-मुक्त ऋण को भी बढ़ावा दिया है, जो ऋण के गारंटीकृत हिस्से के लिए शून्य जोखिम भार वहन करती है।

एमएसएमई को भुगतान में विलंब की समस्या को दूर करने के लिए आरबीआई ने कई नवाचार शुरू किए हैं। व्यापारिक प्राप्य-राशि भुनाई प्रणाली (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम - TReDS), इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमएसएमई के व्यापार प्राप्य वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करता है। एकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क और एए पारितंत्र में जीएसटीएन को शामिल करने से एमएसएमई ऋण के लिए वित्तीय डेटा तक पहुंच आसान हो गई है। हाल ही में, अगस्त 2023 में पायलट कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई), एमएसएमई को डिजिटल डेटा का उपयोग करके प्रयोजन-विशिष्ट, निर्बाध ऋण प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने ₹25 करोड़ तक के एमएसएमई ऋणों के लिए पुनरुत्थान और पुनर्वास ढांचा लागू किया है, जो दबाव-मुक्ति के लिए एक सदा-सुलभ संरचित तंत्र प्रदान करता है। क्षमता निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, आरबीआई एनएएमसीएबीएस (NAMCABS)[4] कार्यक्रम भी चलाता है, जो बैंकरों को एमएसएमई क्षेत्र की विशिष्ट ऋण आवश्यकताओं से परिचित कराता है, जिससे एमएसएमई वित्तपोषण के लिए उनकी समझ और समर्थन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

मुद्रा और सीजीटीएमएसई जैसी सरकारी योजनाओं के साथ-साथ, इन प्रयासों ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए औपचारिक ऋण में उल्लेखनीय सुधार किया है। 31 मार्च 2024 तक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एमएसएमई को दिया जाने वाला बकाया ऋण ₹27.25 लाख करोड़ था, जो औपचारिक वित्तीय पारितंत्र में एमएसएमई के बढ़ते एकीकरण को दर्शाता है। यह जानकर प्रसन्नता होती है कि पिछले दो वित्तीय वर्षों में एमएसएमई के लिए बकाया बैंक ऋण में क्रमशः 12.39 और 20.58 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है।

एमएसएमई क्या कर सकते हैं?

जबकि विनियामक नीतियों और सरकारी योजनाओं ने एमएसएमई के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एमएसएमई के लिए यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वे विश्वास स्थापित करने और ऋणदाताओं के साथ उनकी प्रत्यक्षता बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठाएं। इस संदर्भ में, मेरे पास चार प्रमुख सुझाव हैं जिन पर एमएसएमई को वित्त तक बेहतर पहुंच के साथ-साथ अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विचार करना चाहिए।

औपचारिकता अपनाएं

सर्वप्रथम, एमएसएमई को औपचारिकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। कई एमएसएमई अनौपचारिक रूप से काम करते हैं, जिससे ऋणदाताओं के लिए सूचना विषमता के कारण उनकी ऋण पात्रता का आकलन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, विशेषकर उनके वित्तीय प्रदर्शन के संबंध में। उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण करके और जीएसटी रिटर्न भर करके, एमएसएमई अपनी कारोबारी गतिविधि और वित्तीय स्थिति के स्तर पर पारदर्शिता बढ़ा सकते हैं। इससे उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और वित्तीय संस्थाओं की नज़र में उनकी विश्वसनीयता को मजबूत करके उन्हें प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार और सरकारी योजनाओं के लिए योग्य बनाया जा सकता है।

औपचारिकता को अपनाने के साथ-साथ, एमएसएमई को समग्र और सटीक वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए जो उधारदाताओं के साथ विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। एमएसएमई को उचित लेखांकन प्रथाओं को अपनाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके वित्तीय रिकॉर्ड, जैसे आय विवरण, तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) और नकदी प्रवाह विवरण सटीक और विश्वसनीय हैं। प्रमाणित पेशेवरों द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरण और योग्य लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किए जाने से उनकी विश्वसनीयता और भी बढ़ जाएगी।

औपचारिकता के साथ-साथ, यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अपनाने से वित्तीय लेनदेन का डिजिटल फुटप्रिंट बनता है, जिससे ऋणदाताओं के लिए फर्म की वित्तीय स्थिति का आकलन करना आसान हो जाता है।

[4] बैंकरों की क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय मिशन

डिजिटल भुगतान नकदी प्रवाह प्रबंधन में भी सुधार करते हैं, जिससे एमएसएमई को अपने वित्त पर अधिक नियंत्रण मिलता है और उन्हें स्पष्ट वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिलती है।

क्रेडिट अनुशासन

दूसरे, एमएसएमई को और भी अधिक क्रेडिट अनुशासन के लिए प्रयास करना चाहिए जो उनकी आवश्यकताओं और नकदी प्रवाह के अनुकूल उचित ऋण उत्पाद के सावधानीपूर्वक चयन से शुरू होता है। एमएसएमई को अपनी उधारी आवश्यकताओं के अनुरूप ऋण उत्पादों से मिलान करने के लिए मीयादी ऋण, कार्यशील पूंजी ऋण, ओवरड्राफ्ट और इनवॉइस डिस्काउंटिंग जैसे विभिन्न ऋण उत्पादों से स्वयं को परिचित कराना चाहिए। व्यापार चक्रों के अनुसार उधार लेना और अधिक-लीवरेजिंग से बचना महत्वपूर्ण है। ऋणदाताओं के बीच शर्तों की तुलना करना और बेहतर ब्याज दरों और पुनर्भुगतान विकल्पों के लिए बातचीत करना अधिक अनुकूल ऋण शर्तों के परिणामस्वरूप हो सकता है। इसके अलावा, औपचारिक वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए एक अच्छे क्रेडिट स्कोर का होना और उसे बनाए रखना महत्वपूर्ण है। एमएसएमई को ऋण और बिलों का समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए, जो उनके क्रेडिट इतिहास पर धनात्मक रूप से प्रतिबिंबित होता है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि बैंक की निधियों का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया जाए, जिनके लिए इसे उधार लिया गया था। हालांकि, कभी-कभी यह देखा जाता है कि कार्यशील पूंजी निधि को अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया जाता है। कुछ लोग अपनी इक्विटी का पूरा निवेश नहीं करते पाए गए हैं या बैंकों से उधार ली गई निधि को अपने कारोबार से बाहर के उद्देश्यों के लिए डायवर्ट करते पाए गए हैं। कई बार, अनियोजित और अनुचित तरीके से वित्तपोषित क्षमता या बाजार विस्तार, दबाव का एक प्रमुख स्रोत बन चुके हैं, जिससे क्रेडिट इतिहास और इस तरह उनके बैंकों के साथ विश्वसनीयता प्रभावित होती है। ये सभी पूरी तरह से टाले जा सकते हैं, नैतिक और विवेकपूर्ण तरीके से कारोबार करने से ऐसी अदूरदर्शी कार्रवाइयों पर काबू पाने में मदद मिलती है।

क्षमता निर्माण

तीसरा, एमएसएमई को अपने परिचालन और वित्तीय प्रबंधन कौशल को मजबूत करने के लिए क्षमता निर्माण में निवेश करना चाहिए। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, उद्यमियों को ऋण मूल्यांकन प्रक्रियाओं, बैंकिंग मानदंडों और सरकारी सहायता उपायों को समझने में मदद करते हैं, जिससे उधारकर्ता के रूप में उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। अनुपालन, बहीखाता पद्धति और बाजार के रुझान जैसे विषयों पर कौशल विकास कार्यशालाएँ, उन्हें अपने कारोबार और वित्त का बेहतर प्रबंधन करने के लिए तैयार करती हैं।

एमएसएमई क्षमता निर्माण और वित्तपोषण के लिए पारितंत्र का लाभ उठा सकते हैं। उद्योग निकायों और व्यापार संघों के साथ जुड़ने से एमएसएमई को संरक्षण, वित्तपोषण के अवसर और बाजार संपर्क मिलते हैं। इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर के साथ सहयोग से प्रशिक्षण, नेटवर्किंग और वित्तपोषण तक पहुँच मिल सकती है। इसके अतिरिक्त, बिक्री पैटर्न या आपूर्तिकर्ता प्रतिक्रिया के आधार पर वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग का उपयोग करने वाले फिनटेक समाधान, एमएसएमई को अधिक प्रभावी ढंग से वित्तपोषण प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं।

चतुर्थ, एमएसएमई को टीआरईडीएस के उपयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए जो बड़े खरीदारों को प्रस्तुत किए गए बिलों को भुना कर कार्यशील पूंजी तक पहुंच के लिए एक मंच प्रदान करता है। खरीदारों को भी टीआरईडीएस पर लाने से लेनदेन प्रक्रिया में आसानी होती है और समय पर भुगतान होता है। एमएसएमई अपने परिचालन में टीआरईडीएस को एकीकृत करके, चलनिधि को अनलॉक कर सकते हैं, नकदी प्रवाह में सुधार कर सकते हैं और उधारदाताओं के साथ मजबूत विश्वास बना सकते हैं।

मैं समझता हूँ कि आज हमारे बीच कुछ बैंकर भी मौजूद हैं। यद्यपि आरबीआई पृथक रूप से बैंकिंग समुदाय के साथ संवाद करता है, विशेष रूप से एमएसएमई पर स्थायी सलाहकार समिति के तहत, मैं इस अवसर पर एमएसएमई के लिए वित्तपोषण में सुधार के महत्व पर जोर देना चाहूँगा। ऋण अंतर को पाटना केवल एकल एमएसएमई के विकास का समर्थन करने के बारे में नहीं है; यह एक ऐसे क्षेत्र को सशक्त बनाने के बारे में है जो एक समुत्थानशील और गतिशील अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वित्त तक बेहतर पहुँच के साथ, एमएसएमई नवोन्मेष को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और देश भर में समुदायों के उत्थान के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। यह भारत के लिए अधिक समावेशी और धारणीय भविष्य के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए, मैं बैंकरों से एमएसएमई के साथ मिलकर काम करने का आग्रह करूँगा ताकि विश्वास स्थापित हो, ऋण अनुशासन बढ़े और यह सुनिश्चित हो कि वे सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों से लैस हैं।

निष्कर्ष के तौर पर, एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए सभी हितधारकों - सरकार, विनियामक निकायों, वित्तीय क्षेत्र, व्यापार संघों और यहां तक कि बड़े कॉरपोरेट्स के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। आर्थिक वृद्धि को गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें भुगतान में देरी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधाएं, औपचारिक वित्त तक सीमित पहुंच, प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर को अपनाना और कुशल श्रम शक्ति की कमी शामिल हैं। आरबीआई ने इन मुद्दों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है, ऋण तक पहुंच को आसान बनाया है और डिजिटलीकरण की वकालत की है। जबकि आरबीआई और सरकार ने एक मजबूत नीति ढांचा स्थापित किया है, जिसमें प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देना, संपार्श्विक-मुक्त ऋण, टीआरईडीएस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्षमता निर्माण की पहलें शामिल हैं, एमएसएमई के लिए इन अवसरों का अधिक-से-अधिक लाभ उठाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आगे चलकर, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के निरंतर विकास और समुत्थानशीलता को सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के बीच निरंतर सहयोग महत्वपूर्ण होगा।

इसके साथ ही, मैं फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए हैदराबाद आमंत्रित किया। मैं फेडरेशन को इस तरह के सुव्यवस्थित आयोजन के लिए बधाई देता हूं।

धन्यवाद।